'अप्प दीपो भव'

# वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.09.2015
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: aicscst@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 20 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 सितम्बर, 2015

# कानपुर मंडल परिसंघ का ऐतिहासिक सम्मेलन सम्पन्न

## सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने उ.प्र. सरकार द्वारा लाखों की संख्या में दलित कर्मियों की पदावनति (डिमोशन) करने एवं दलितों की जमीन अन्य सभी वर्गों को बेचे जाने के निर्णय के खिलाफ डॉ. उदित राज जी के नेतृत्व में जन आंदोलन में पूरा सहयोग करेगा

6 सितंबर, 2015 को छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर नगर, के मुख्य सभागार में परिसंघ की मंडल इकाई द्वारा ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 1997 से 2012 तक आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नति प्राप्त कर चुके कर्मचारियों/अधिकारियों को लाखों की संख्या में पदावनत किया जा रहा है और साथ ही विधान सभा में अनुसूचित जाति/जन जाति की जमीनों का अन्य वर्गों को बेचे जाने संबंधी लिए गए निर्णय के विरुद्ध भी गांव–देहात के लोग भी परिसंघ से जुड़ने लगे हैं, क्योंकि परिसंघ के चेयरमैन ने इस मुद्दे को अपने जन–आंदोलन में जोड़ने का ऐलान कर दिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिसंघ के चेयरमैन एवं लोक सभा सदस्य, माननीय डॉ0 उदित राज जी थे तथा अध्यक्षता परिसंघ के राष्ट्रीय समन्वयक एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 श्री जगजीवन प्रसाद जी ने की तथा विशिष्ट अतिथियों में परिसंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष – बी.डी. भारती एवं राधेश्याम, प्रदेश सचिव – के.पी. चौधरी, राम अवतार, पंचम लाल, कानपुर मंडल के संरक्षक – बी.एल. सोनकर, उ0प्र0 परिसंघ के प्रधान महासचिव – धर्म सिंह सहित कई मंडलों व जिलों के अध्यक्ष मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना से प्रारंभ हुई और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर तथा बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एवं संत कबीर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर डॉ0 उदित राज जी ने सभा की विधिवत् कार्यवाही की शुरुआत की। परिसंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष – बी.डी. भारती जी ने अपने संबोधन में अकेले दम पर दस हजार परिसंघ के सदस्य बनाने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। बाद में दूसरे प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री राधेश्याम जी ने अपने जनपद औरैया एवं इटावा आदि में सैकड़ो आजीवन सदस्य बनाए जाने का और साधारण सदस्य बनाए जाने की बात कही और 1 नवंबर, 2015 को लखनऊ में प्रांतीय महारैली में बढ़–चढ़कर हर संभव सहयोग और अधिक से अधिक साथियों के साथ पहुंचने का आश्वासन दिया। परिसंघ के प्रदेश सचिव – श्री के.पी. चौधरी ने दलितों को बौद्ध प्रमाण–पत्र न बनाए जाने की जानकारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को दी और उन्होंने भी हर संभव आर्थिक सहायता एवं भीड़ जुटाने का आश्वासन दिया। इसके बाद दूसरे प्रदेश सचिव, श्री राज कुमार गौतम, श्री पंचम लाल, श्री राम अवतार तथा श्री महेन्द्र कुमार गौतम, ने भी सभा को संबोधित किया और अपने स्तर से धन एवं जन से सहयोग करने की घोषणा की। हरदोई के पुराने साथी श्री लाल बिहारी जी ने सभा को अपनी कविताओं के माध्यम से सभी को हंसा–हंसाकर भाव–विभोर करते रहे और कार्यक्रम की सार्थकता को बताते रहे तथा हरदोई के जिलाध्यक्ष, श्री अमित राज जी ने बताया कि वे हजारों की संख्या में लोगों को तैयार करते हैं, लेकिन चलते–चलते सैकड़ों में ही लोग कार्यक्रम में पहुंच पाते हैं, इस बात को सुनकर मुख्य अतिथि सहित सभी को हंसी आ गयी और डॉ0 उदित राज जी कहने लगे कि अमित राज जी ने असलियत बता दी।

औरैया के जिलाध्यक्ष, श्री नीरज कुमार चक को विशेष सम्मान के साथ मंच पर बुलाया गया, क्योंकि दूर के जिलों से सबसे अधिक लगभग 250 लोगों को लेकर 2 बसों एवं 3 चार पहिया गाड़ियों के साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ0 उदित राज जी के आगमन के समय अपने सभी साथियों के साथ बाहरी गेट से सभा के मुख्य द्वार तक नारे लगाते हुए आए।

उ0प्र0 परिसंघ के प्रधान

(शेष पृष्ठ 2 पर)

साथियो, आरक्षण खत्म करने की साजिश गुजरात के पटेल नेता, हार्दिक पटेल ने पांच लाख लोगों की रैली से की। पटेल सबसे ज्यादा अमीर हैं। अब भ्रम नहीं होना चाहिए कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। पहले हम लोग ऐसा कहते थे और अब सरकार में लगभग 40 प्रतिशत खत्म भी हो गया है, तो क्या कर लिया। क्लास 4 की भर्ती खत्म, आउटसोर्सिंग और एडहाक के जरिए ऐसा कर दिया गया है। पदोन्नति में आरक्षण का बिल पास नहीं हो पाया है। उ0प्र0 में डिमोशन शुरू हो गया है। आरक्षण बचाना हो तो हमें 10 लाख लोगों की रैली करनी होगी। इसलिए अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा आगामी 7 दिसंबर, 2015 को प्रातः 10 बजे रामलीला मैदान, नई दिल्ली में लाखों की संख्या में पहुंचे। हमें लाखों मिश्नरियों के नाम और मोबाइल नम्बर वाट्सअप और मेल के जरिए फौरन भेजें। ताकि हम उनसे भी बात कर सकें और रैली सफल हो। हमारा वाट्सअप नं. 9999504477 एवं ईमेल parisangh1997@gmail.com है।

– डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन

# नसोएवायएफ का बुन्देलखण्ड अधिवेशन सम्पन्न

नेशनल एस.एसी.,एस.टी., ओबीसी स्टूडेन्ट एण्ड यूथ फ्रंन्ट (नसोसवायएफ) का प्रथम बुन्देलखण्ड अधिवेशन 7 सितम्बर को मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में संपन्न हुआ इस अधिवेशन का उद्घाटन डॉ. उदित राज, सांसद एवं राष्ट्रीय चेयरमैन, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनो का अखिल भारतीय परिसंघ, स्वागताध्यक्ष आर.डी. प्रजापति (विधायक), कार्यक्रम अध्यक्ष नसोसवायएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. हर्षवर्धन एवं कार्यक्रम अयोजक अध्यक्ष नसोसवायएफ के राष्ट्रीय समन्वयक प्रताप सिंह अहिरवार थे। इस अवसर पर छात्र और युवाओं को संम्बोधित करते हुए डॉ. उदित राज जी ने कहा कि भारत के सभी शिक्षा संस्थान सामाजिक परिवर्तन एवं समतामूलक समाज निर्माण करने में असफल रहे हैं। देश में जातिवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, भूमण्डलीकरण और निजीकरण के दौर में दलित-आदिवासी अधिकार खत्म किये जा रहे हैं। निजीकरण के माध्यम से दलित-आदिवासी, ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है और हमारा समाज खामोश बैठा है, ऐसे वक्त में छात्र और युवाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। छात्र और युवाओं को अभी तक कोई राष्ट्रीय मंच नहीं था। किसी दलित-आदिवासी नेता ने मंच आज तक उपलब्ध नहीं करके दिया, यह गलती हुई है, मगर आज नसोसवायएफ जैसा राष्ट्रीय संगठन अनुसूचित जाति/ जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के द्वारा खड़ा किया गया है। हम चाहते हैं कि छात्र पढ़ाई के लिए लड़ाई करें, क्योंकि इस देश की शिक्षा व्यवस्था समान स्वरूप की नहीं है। इसके कारण सभी को शिक्षा का समान अवसर देश में प्राप्त नहीं होता है। अगर शिक्षा का समान अवसर दलित-आदिवासियों को प्राप्त नहीं होता तो सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो सकता यह वास्तविकता है और इसी करण देश की आज़ादी के 68 साल के बाद भी दलितों-आदिवासियों का सामाजिक, आर्थिक विकास नहीं हो पाया। डॉ. उदित राज जी ने सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में 40 प्रतिशत से भी ज्यादा आरक्षण खत्म हुआ है, इसलिए अब वक्त है कि निजीक्षेत्र में आरक्षण देना इसके लिए देश के छात्र और युवा नसोसवायएफ के माध्यम से संगठित किया जाए और अपने सामाजिक न्याय के अधिकार के लिए निजीक्षेत्र, सेना व न्यायपालिका में आरक्षण आंदोलन को अब अनजाम देना होगा। जो छात्र युवा प्रतियोगीता परीक्षा में दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और सामजिक आंदोलन से हटकर अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं वे छात्र और युवा उन सभी को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। इस भ्रामक कल्पना से बाहर आएं और अपनी नौकरियों के लिए अपनी शिक्षा के लिए सामजिक आंदोलन की पेशकश करें, इसके सिवा दलितों-आदिवासियों का और कोई जरिया नहीं है। डॉ. उदित राज जी ने नसोसवायएफ के इस अधिवेशन में छात्र और युवाओं को 7 दिसम्बर, 2015 को रामलीला मैदान पर होने वाली रैली में बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी आवाज बुलन्द करने का अवाहन किया है।

देश में बहुत सारे छात्र संगठन हैं, मगर ये सभी छात्र संगठन प्रस्थापित विचारधारा पर कार्य करते हैं, कोई गांधीवादी है, कोई हिन्दुवादी है तो कोई मार्क्सवादी छात्रसंगठन है। मगर ये संगठन कभी दलित-आदिवासी छात्रों के लिए आंदोलन खड़ा नहीं करते इन छात्र संगठनों की ताकत दलित- आदिवासी छात्र हैं, मगर दलित- आदिवासी की शिक्षा में आरक्षण की नीति के विरोध में छात्र संगठन दिखाई नहीं देता है, इसलिए नेशलन एस.सी./एस.टी./ओबीसी स्टूडंन्टस् एण्ड यूथ फ्रन्ट (नसोसवायएफ) की देश में दलित-आदिवासी छात्रों को जरूरत है। देश में आरक्षण विरोधी माहौल बनता जा रहा है। सवर्ण छात्र आरक्षण के खिलाफ हमेशा दिखाई देते हैं, मण्डल आयोग लागू करने के बाद दिल्ली कॅम्पस में आरक्षण विरोधी छात्रों ने जो आंदोलन किया उसका मुकाबला आरक्षण समर्थक छात्र कर नहीं पाये। ये बड़ी दुखद बात है। प्रस्थापित व्यवस्था आपके अधिकार छीनने के लिए मारने और मरने के लिए तैयार हैं। मगर अपने हक बचाने के लिए दलित-आदिवासी छात्र के पास कोई राष्ट्रीय संगठन पहले नहीं था। पर आज नसोसवाएफ जैसा राष्ट्रीय अंम्बेडकरवादी संगठन आज आरक्षण के समर्थन में दलित-आदिवासी, ओबीसी, छात्रों को संगठित कर रहा है। देश के छात्र, युवा इस संगठन से जुड़ कर आरक्षण विरोधियों को मुहंतोड़ जवाब दे सकते हैं।

भूमण्डलीकरण, निजीकरण के इस दौर ने सरकारी नौकरियों में से 40 प्रतिशत आरक्षण खत्म किया है। एसे वक्त में निजीक्षेत्र में आरक्षण के आंदोलन को ओर तेज करना पड़ेगा। देश की सभी दलित-आदिवासी छात्रों की पहली जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आरक्षण से ही देश में दलित-आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है और निजीकरण से आरक्षण अगर खत्म होता है तो दलित -आदिवासी वही 70 साल पीछे चले जायेंगे और गुलाम बनेगें।

सम्मेलन में अपार जनसमूह के साथ डॉ0 उदित राज एवं प्रताप सिंह अहिरवार

डॉ. उदित राज ने अपने संबोधन के आखिर में दलित-आदिवासीयों के शिक्षा, रोजगार, अधिकार और सम्मान की लाईई को नसोसवासएफ द्वारा और तेज बनाने को कहा। ''शिक्षित बनो, और शिक्षा के लिए लड़ो।'' ''नई सदी की नई लड़ाई, करो पढ़ाई लढ़ो लड़ाई।'' ये नारा देकर सभी छात्र और युवा को एक संदेश दिया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष डी. हर्षवर्धन (राष्ट्रीय अध्यक्ष, नसोसवायएफ) ने कहा कि इस संगठन का महाराष्ट्र राज्य से देश भर में विस्तार हो रहा है। और असमान शिक्षा व्यवस्था, जातिवाद और गरीबी से परेशान शोषक और पिड़ित छात्र सवर्णो के व्यवस्था के खिलाफ नसोसवायएफ के माध्यम से पुकार रहा है। वर्तमान स्थिति में हार्दिक पटेल और पटेल जाति को आरक्षण मांगने हेतु दलित आदिवासी के आरक्षण खत्म करने का षडयंत्र देश भर में किया जा रहा है। हार्दिक पटेल जैसा प्रवीण तोगड़ीया के चमचे को नसोसवायएफ मुंहतोड जवाब देगा। निजीक्षेत्र में आरक्षण यह दलित-आदिवासी के रोजगार और भविष्य का सवाल है। इस सवाल पर दलित आदिवासी युवकों को संघर्ष करना पड़ेगा। नसोसवायएफ का संघर्ष जातिव्यवस्था के खिलाफ है और सामंतवाद से परेशान युवकों का है।

नसोसवायएफ एक अम्बेडकर विचारों का जाति-विहीन समता-मूलक समाज राज्य समाजवादी निर्माण के लिए एक विद्रोह है और नसोसवायएफ के सभी छात्र इस प्रस्थापति व्यवस्था के विरोधी हैं।

इस अधिवेशन में प्रताप सिंह अहिरवार ने कहा बुन्देलखण्ड देश का पिछड़ा इलाका होकर यहां जातिवाद हर एक वक्त के रोम-रोम में बैठा हुआ है। इस संभाग में जातीय शोषण बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में नसोसवायएफ हर एक गांव और मोहल्ले में जाकर छात्र और युवाओं को संगठित करने का कार्य कर रहा है, इस कार्य में बुन्देलखण्ड के छात्र एवं युवा संगठित हुए हैं। नसोसवायएफ देश में एक क्रांति लाना चाहता है और इस क्रांति के अधिवेशन में शामिल हुए सभी क्रांतिकारी हैं। अधिवेशन को सफल बनाने के लिए ए. सेन्डी, प्रकाश अहिरवार, भुपेंद्र अहिरवार, रतीराम अहिरवार, रविन्द्र कुमार, मुकेश अहिरवार, मुन्ना लाल, भागचन्द्र, बृजेश, आनंद, एड. अरविंद कुमार, बाल्मीकि, पन्ना लाल, मुकेश गांधी, नितेन्द्र चौरसिया, सुनील वर्मा, बृज किशोर, रामअवतार, गंगारामजी, भारती, अनुरागी आदि ने परिश्रम किया।

+++

(पृष्ठ 1 का शेष)

## कानपुर मंडल परिसंघ का ऐतिहासिक सम्मेलन .....

महाचिव, श्री धर्म सिंह जी ने अपने संबोधन में यह कहा कि सुश्री मायावती जी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से ज्यादा गुनाहगार हैं। यदि वे चाहती तो माननीय सर्वोच्च न्यायायल के निर्देशों के अनुसार दूसरे प्रदेशों की भांति कमेटी बनाकर कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण लागू कर सकती थी, लेकिन वे सवर्ण वोट पाने की खातिर आरक्षित कर्मचारियों का बंटाधार कर दिया है और झांसी मंडल में आगामी 17 अक्टूबर, 2015 को महासम्मेलन करने की घोषणा की। इसी बीच सभा अध्यक्ष एवं परिसंघ के पदेशाध्यक्ष, श्री जगजीवन प्रसाद जी ने दूसरे पहलू पर अपने विचार रखते हुए बताया कि उ0प्र0 सरकार सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के अध्यक्ष की इस घोषणा पर मौजूदा सरकार बहुमत में आ गयी कि वे दलितों को पदोन्नति में आरक्षण देना बंद कर दें। यह उ0प्र0 सरकार की नासमझी ही कही जाएगी। उनके अनुसार दलित सुश्री मायावती जी की कार्यशैली से नाराज थे, इसलिए मुलायम सिंह जी की पार्टी को वोट कर दिया लेकिन उ0प्र0 की मौजूदा सरकार दलितों के साथ जिस तरह की हरकत कर रही है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। अभी कई वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्बोधन होना बाकी था। इसी बीच हाल में बैठे लोगों की तरफ से यह आवाज आने लगी कि हम लोग डॉ0 उदित राज जी को सुनना चाहते हैं। इस बारे में सभा के मुख्य कर्त्ता-धर्ता श्री सुशील कुमार कमल जी भी मंच पर आकर डॉ0 उदित राज जी से अनुरोध किया कि यदि वे जल्दी नहीं बोलेगें तो लोग चले जाएंगें। जल्दी-जल्दी में सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को संबोधन हेतु बुलाया गया और डॉ0 उदित राज का उद्बोधन शुरू हुआ। उन्होंने कानपुर मंडल के पदाधिकारियों एवं प्रमुख रूप से श्री सुशील कुमार कमल - मंडल अध्यक्ष की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए बताया कि उनके नेतृत्व में परिसंघ के जन-आंदोलन के जरिए आरक्षण बचाने का इतिहास रहा है। उन्होंने 1997 से अब तक अपने पूरे जन आंदोलन की विस्तार से चर्चा की। उनका भाषण लगभग 2 घंटे 15 मिनट तक चला और लोगों ने बड़े ध्यान से मुख्य अतिथि का भाषण सुना और सैकड़ों लोगों ने उनकी स्पीच की सीडी की मांग करने लगे। उन्होंने लोक सभा में पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर 31 जुलाई 2015 को शून्यकाल के दौरान उठाए गए मुद्दे पर बोलते हुए बताया कि उन्होंने जितने प्रश्न और मुद्दे लोक सभा में उठाए हैं, शायद कुल दलित सांसदों ने भी मिलकर इतने मुद्दे नहीं उठाए होगें। उन्होंने 1 नवम्बर, 2015 को लखनऊ में घोषित महारैली तथा 7 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली को तन-मन-धन से सहयोग करने की बात कही और आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में 117वें संवैधानिक संशोधन बिल को पास करवाकर उ0प्र0 के दलित कर्मचारियों-अधिकारियों को न्याय दिलाएंगें, बशर्ते उनका सहयोग मिलता रहे।

कानपुर मंडल के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के आयोजक सुशील कुमार कमल जी ने सभागार में सभी साथियों को धन्यवाद दिया और जिन्होंने इस कार्यक्रम में आर्थिक एवं बौद्धिक सहयोग किया उनका नाम गिनाते हुए उपस्थित जन समूह से पदोन्नति में आरक्षण एवं दलितों की जमीन बचाने के लिए किसी भी स्तर के जन-आंदोलन के लिए तैयार रहें। उन्होंने प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए विशेष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले सर्वश्री भारत लाल, बी.एन. कमल, परिसंघ के जिलाध्यक्ष कानपुर नगर - श्री हरिजीवन, अवनीश कुमार सोनकर, जितेन्द्र कमल, रमेश चंद बाल्मीकि, सुदामा, मोहल लाल, अश्विनी कुमार बाल्मीकि, महेश मलिक आदि लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

- जगजीवन प्रसाद
अध्यक्ष, उ0प्र0 परिसंघ

# नेशनल एस.सी. एस.टी. ओबीसी स्टुडेन्टस् एण्ड युथ फ्रंट (नसोसवायएफ) महाराष्ट्र राज्य का प्रथम अधिवेशन संपन्न

नेशनल एस.सी. एस.टी. ओबीसी स्टुडेन्टस् एण्ड युथ फ्रंट (नसोसवायएफ) महाराष्ट्र राज्य का प्रथम अधिवेशन 13 सितम्बर को महाराष्ट्र के नांदेड शहर में पूरे जोश के साथ संपन्न हुआ। इस अधिवेशन का उद्घाटन, डॉ. उदित राज जी, सांसद व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ एवं मुख्य मार्गदर्शक नसोसवायएफ थे। कार्यक्रम के स्वातगताध्यक्ष डॉ. संतुक हंबर्डे एवं कार्यक्रम अध्यक्ष डी. हर्षवर्धन जी थे।

इस अधिवेशन में उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज ने कहा कि वर्तमान शिक्षा नीति से कोई विकास नहीं होगा। शिक्षा नीति में सामजिक परिवर्तन करने वाले पाठ्यक्रम को आज तक कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। स्कूल, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में जातिवाद और लिंग भेद खत्म करने की शिक्षा दी नहीं गई। इसलिए आज भी जातिव्यवस्था कायम है और सवर्ण जाति के छात्र अपनी जाति का अंहकार विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दिखाते हैं। इससे विश्वविद्यालय और विद्यालयों में जाति-व्यवस्था और ताकतवर बनती जा रही है। आज तक हमारे शिक्षा संस्थानों को जाति व्यवस्था खत्म करनी चाहिए थी और देश में समता लानी चाहिए थी लेकिन यह सिखाई ही नहीं गई। इसलिए देश का सामाजिक विकास संपूर्ण रुप से नहीं हो पाया। नसोसवायएफ के द्वारा विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम बदलकर सामाजिक परिवर्तनवादी विचारों के पाठ्यक्रम की मांग करनी चाहिए।

देश में बहुत सारे छात्र संगठन है, मगर वे सभी छात्र संगठन प्रस्थापित विचारधारा पर कार्य करते हैं, कोई गांधीवादी है, कोई हिन्दूवादी है तो कोई मार्क्सवादी छात्र संगठन है। मगर ये संगठन कभी दलित-आदिवासी छात्रों के लिए आंदोलन खड़ा नहीं करते। इन छात्र संगठनों की ताकत दलित-आदिवासी छात्र हैं, मगर दलित- आदिवासी की शिक्षा में आरक्षण की नीति के खिलाफ छात्र संगठन दिखाई नहीं देता है, इसलिए नेशलन एस.सी./एस.टी./ओबीसी स्टूडेंन्टस् एण्ड यूथ फ्रन्ट (नसोसवायएफ) की देश में दलित-आदिवासी छात्रों को जरुरत है। देश में आरक्षण विरोधी माहौल बनता जा रहा है। सवर्ण छात्र आरक्षण के खिलाफ हमेशा दिखाई देते हैं। मण्डल आयोग लागू करने के बाद दिल्ली कैम्पस में आरक्षण विरोधी छात्रों ने जो आंदोलन किया, उसका मुकाबला आरक्षण समर्थक छात्र कर नहीं पाये। ये बड़ी दुखद बात है। प्रस्थापित व्यवस्था आपके अधिकार छीनने के लिए मारने और मरने के लिए तैयार है। मगर अपने हक बचाने के लिए दलित-आदिवासी छात्र के पास कोई राष्ट्रीय संगठन पहले नहीं था। पर आज नसोसवायएफ जैसा राष्ट्रीय अंम्बेडकरवादी संगठन आरक्षण के समर्थन में दलित-आदिवासी, ओबीसी, छात्रों को संगठित कर रहा है। देश के छात्र, युवा इस संगठन से जुड़ के आरक्षण विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं।

भूमण्डलीकरण, निजीकरण के इस दौर ने सरकारी नौकरियों में से 40 प्रतिशत आरक्षण खत्म किया है। ऐसे वक्त में निजीक्षेत्र में आरक्षण के आंदोलन को ओर तेज करना पड़ेगा। देश की सभी दलित-आदिवासी छात्रों की पहली जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आरक्षण से ही देश में दलित-आदिवासीयों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है और निजीकरण से आरक्षण अगर खत्म होता है तो दलित -आदिवासी वही 70 साल पीछे चले जाएंगें।

डॉ. उदित राज ने अपने संबोधन में आखिर में दलित-आदिवासियों के शिक्षा, रोजगार, अधिकार और सम्मान की लाइई को नसोसवासएफ द्वारा और तेज करने को कहा। "शिक्षित बनो, और शिक्षा के लिए लड़ो।" "नई सदी की नई लड़ाई, करो पढ़ाई लड़ो लढाई।" ये नारा देकर सभी छात्र और युवा को एक संदेश दिया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष डी. हर्षवर्धन (राष्ट्रीय अध्यक्ष, नसोसवायएफ) ने कहा की इस संगठन का महाराष्ट्र राज्य से देश भर में विस्तार हो रहा है। असमान शिक्षा व्यवस्था, जातिवाद व गरीबी से परेशान शोषक और पीड़ित छात्र सवर्णो के व्यवस्था के खिलाफ नसोसवायएफ के माध्यम से एकजुट हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति में हार्दिक पटेल और पटेल जाति द्वारा आरक्षण की मांग, दलित आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने का षडयंत्र पूरे देश में किया जा रहा है। हार्दिक पटेल जैसे प्रवीण तोगड़ीया के चमचे को नसोसवायएफ मुंहतोड़ जवाब देगा। निजीक्षेत्र में आरक्षण दलित-आदिवासियों के रोजगार और भविष्य का सवाल है। इस सवाल पर दलित-आदिवासी युवकों को संघर्ष करना पड़ेगा। नसोसवायएफ का संघर्ष जातिव्यवस्था के खिलाफ और सामंतवाद द्वारा सताए गए युवकों का है।

नसोसवायएफ एक अम्बेडकरवादी विचारों का जाति-विहीन समतामूलक समाज की स्थापना करने वाला संगठन है और नसोसवायएफ के सभी छात्र इस जाति-व्यवस्था के विरोधी हैं।

इस कार्यक्रम के लिए नसोसवायएफ के राष्ट्रीय महासचिव अजय पासवान (पटना, बिहार), राष्ट्रीय समन्वयक प्रताप सिंह अहिरवार (छतरपुर, मध्य प्रदेश), चेराबंडू राजू (आंध्रा प्रदेश-तेलंगना समन्वयक), महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा भावना इलपाची (नागपुर), महाराष्ट्र प्रभारी बालाजी कोंडामंगल (नांदेड), अजित कांबळे (कोल्हापुर), महाराष्ट्र राज्यसचिव रवि सुर्यवंशी, महाराष्ट्र सहसचिव स्वप्निल मुळे, किशोर कानिंदे (मुंबई), लक्ष्मण मीना (राजस्थान), हर्षवर्धन मोरे (सोलापुर), गणेश येरेकर (नांदेड) आदि ने छात्राओं को असमान शिक्षा व्यवस्था और उस पर होने वाला दलित-आदिवासियों पर परिणाम और निजीक्षेत्र में समान आरक्षण और अनिवार्य शिक्षा-व्यवस्था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी व्यवस्था 2011 में होने वाला परिणाम के संबंध में चर्चा की।

इस अधिवेशन के स्वातगाध्यक्ष संतुक हंबर्डे ने सभी मान्यवरों का स्वागत किया और नसोसवायएफ अधिवेशन की अयोजन कमेटी के अध्यक्ष संघरत्न निवडंगे, राज्य प्रवक्ता राहुल सोनाळे, मराठवाड़ा संघटक बालू भाग्यवंत, जिल्हा अध्यक्ष धम्मपाल वाढवे और आयोजन कमेटी सदस्य प्रकाश पिदके, मंगेश गाडगे, वैभव येरेकर, प्रसेनजित गायवाड़, व्यंकटेश राठोड़, राज्य कमेटी और जिला कमेटी के सभी छात्र कार्य-कर्त्ताओं ने अधिवेशन को सफल बनाने के लिए परिश्रम किया।

- गणेश येरेकर

+++

## आरक्षण का लाभ नेताओं और कर्मचारियों दोनो ने लिया तो इसे बचाने की भी जिम्मेदारी दोनो की

कुछ कर्मचारी-अधिकारी कुछ सांसदों और नेताओं का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि वे पदोन्नति में आरक्षण के मामले को संसद में नहीं उठा रहे हैं। क्या उन कर्मचारियों-अधिकारियों का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए जो स्वयं लड़ाई लड़ना तो दूर उल्टे बकवासबाजी करते रहते हैं ? डॉ0 उदित राज तो एडिशनल कमिश्नर इन्कम टैक्स की पोस्ट से 2003 में इस्तीफा देकर लगभग 10 साल से रोड पर लड़ाई लड़ते रहे बिना किसी पद के, तो क्या उन कर्मचारियों को पहले स्वयं का इस्तीफा देकर तब औरों की मांग नहीं करना चाहिए ? आरक्षण का लाभ नेताओं और कर्मचारियों दोनो ने लिया है, उसमें से एक लड़े और दूसरा मौज-मस्ती करे, अब यह नहीं चलने वाला है। उ0प्र0 में कर्मचारियों के डिमोशन के सवाल पर लाखों कर्मचारियों को इस्तीफा देना चाहिए। सैद्धांतिक और तर्क के आधार पर किसी का नैतिक बल इतना नहीं है कि जो डॉ0 उदित राज को कुछ कह सके। संसद में पहुंचकर डॉ0 उदित राज ने जितने आरक्षण पर सवाल उठाए उतना सारे दलित सांसद मिलकर न कर सके। हार्दिक पटेल को जाति का समर्थन आरक्षण के विरोध में ज्यादा मिला और अपने लिए कम अगर उन्होंने 5 लाख की रैली की तो फौरन उ0प्र0 में डॉ0 उदित राज एवं जगजीवन प्रसाद के नेतृत्व में पहले लाखों की रैली कर देना चाहिए और उसके बाद आगामी 7 दिसंबर को दिल्ली में 10 लाख की। इससे कम अगर हम करते हैं तो जवाब सही नहीं होगा और हम लड़ाई जैसे हार रहे हैं, आगे भी होता रहेगा। जिन कर्मचारियों-अधिकारियों को उ0प्र0 सरकार द्वारा डिमोट किया गया है, उन्हें न घर बैठना चाहिए न ही कार्यालय जाना चाहिए, बल्कि परिसंघ में शामिल होकर संघर्ष को तब तक तेज करना चाहिए जब तक कि अधिकार वापिस नहीं मिल जाते। आइए हम सब मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करें।

निवेदक : अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

ईमेलः parisangh1997@gmail.com व्हाट्सअप नं. 9999504477

# अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ लोक सभा के शीतकालीन सत्र के पहले लखनऊ में आरक्षण के मुद्दे पर महारैली करेगा

5 सितंबर, 2015 को इलाहाबाद में आरक्षण बचाने एवं डिमोट कर्मचारियों-अधिकारियों को न्याय दिलाकर पूर्व की स्थिति में लाने के लिए तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधान सभा में अनुसूचित जाति/जन जाति की जमीन को अन्य वर्गों को बेचे जाने हेतु लिए गए निर्णय के विरोध में एक बड़ी सभा इलाहाबाद नगर के विज्ञान परिषद सभागार, प्रयाग में की गयी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं परिसंघ के चेयरमैन व लोक सभा सदस्य, माननीय उदित राज जी थे। डॉ0 उदित राज जी ने 31 जुलाई, 2015 को लोक सभा में उक्त मुद्दा शून्यकाल के दौरान उठाया था और सरकार से मांग की थी कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों व अधिकारियों का डिमोशन रोका जाए और पदोन्नति में आरक्षण जारी रखा जाए। सरकार कई अन्य मुद्दों पर उलझ गयी और वर्तमान सत्र में आरक्षण से संबंधित बिल नहीं पास हो सका। डॉ0 उदित राज ने बताया कि उनके नेतृत्व में आरक्षण को बचाने के लिए 1997 से जन आंदोलन शुरू किया था और केन्द्र की वाजपेयी सरकार ने दलित हितों में 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन कराकर दलितों का आरक्षण बचाया था और बाद में 85वें संवैधानिक संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी, जिसे एम. नागराज के नाम से जाना जाता है। इस मामले में डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में परिसंघ के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सरकार पर दबाव बनाकर अच्छे अधिवक्ता एवं स्वयं अधिवक्ताओं से पैरवी करवायी गयी। परिणामस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों की बेंच ने कुछ मामूली सुझाव के साथ पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए दलितों के हित में फैसला दिया था। इसी मामले को तत्कालीन बसपा सरकार द्वारा उचित पैरवी न करने के कारण लखनऊ हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण पर 4 जनवरी, 2011 को रोक लगा थी और तत्कालीन सरकार ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले गयी और वहां भी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा।

पदोन्नति में आरक्षण समाप्त होने से, वर्ष 1997 से 2012 तक पदोन्नति पाए हजारों-हजार कर्मचारी-अधिकारी डिमोट किए जा रहे हैं। डॉ0 उदित राज जी ने बताया कि उ0प्र0 को छोड़कर सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए रास्ते पर समिति गठित करके उसकी संस्तुति के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण जारी रखे हुए हैं, मात्र उ0प्र0 की तत्कालीन बसपा सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए डिमोशन हो रहा है। आज जो स्थिति है कि राज्यसभा में पदोन्नति में आरक्षण लागू कराने वाला 177वां संवैधानिक संशोधन बिल पास हो चुका है और लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया और उसके एक सांसद ने सदन के अंदर ही बिल की प्रति फाड़ दी थी। इस बिल को पास करवाकर पदोन्नति में आरक्षण बचाया जा सकता है।

डॉ0 उदित राज जी के नेतृत्व में जन आंदोलन के जरिए दलितों का आरक्षण बचाने का इतिहास रहा है, इसीलिए उन्होंने जन-आंदोलन को अभी तक बंद नहीं किया है तथा उ0 प्र0 सरकार से लगातार मंडलीय एवं जिलों में आरक्षण के समर्थन में बड़ी-बड़ी बैठकें एवं रैलियां करना शुरू कर दिया है और इसी मंतव्य के तहत आज इलाहाबाद में मंडलीय सम्मेलन हुआ और कल 6 सितंबर, 2015 को कानपुर मंडल का सम्मेलन छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के मुख्य सभागार में होगा तथा इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में मंडलीय एवं जिला सम्मेलनों के बाद 01 नवंबर, 2015 को लखनऊ में महारैली की जाएगी। सभा की अध्यक्षता कर रहे परिसंघ के राष्ट्रीय समन्वयक एवं प्रदेश अध्यक्ष, उ0प्र0 श्री जगजीवन प्रसाद ने अनुसूचित जाति/जन जाति की जमीनों को अन्य वर्गों को बेचने के लिए उ0प्र0 सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की घोर निंदा की और उन्होंने इस दलित विरोधी काले कानून को लाकर दलितों को भूमिहीन बनाने का षड्यंत्र बताया। उन्होंने इस मुद्दे को भी परिसंघ के जन आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज से अपील की और उन्होंने अपनी सहमति भी दे दी।

4 अगस्त, 2015 को संसद द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम को मजबूत बनाने के लिए अपने संगठनों एवं उपस्थित जनसमूह द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया।

सभा में प्रमुख रूप से सर्वश्री पंचम लाल, शोभनाथ सरोज, कल्यानजी अम्बेडकर, भानु प्रकाश, गौरी शंकर, महेन्द्र सरोज, सूर्यपाल, विशंभर नाथ, इन्द्रपाल, बड़े लाल वर्मा, अरविंद कुमार, रमाकांत, वी.पी. भारती, राजू पासी, इन्द्रेश सोनकर, हृदय नारायण पासी, महेन्द्र सिंह पासी, चंदीलाल, भंते अभयरत्न जी, धर्मेंद्र आर्य, रामू नेता, आर.के. कमल, राहुल सोनकर, भोलानाथ सोनकर तथा उ0प्र0 परिसंघ के उपाध्यक्ष, श्री बी.डी. भारती, प्रदेश सचिव, के.पी. चौधरी तथा दिल्ली प्रदेश परिसंघ की महासिचव डॉ. अंजू काजल सहित पूरे इलाहाबाद मंडल से हजारों लोग उपस्थित थे।

– जगजीवन प्रसाद
अध्यक्ष, उ0प्र0 परिसंघ

+++

इलाहाबाद में पदोन्नति में आरक्षण हेतु आयोजित जन सभा में मंच पर डॉ0 उदित राज, जगजीवन प्रसाद, अंजू काजल के साथ अन्य वरिष्ठ नेतागण

## वैज्ञानिकों ने खोजी इंसानों की नई प्रजाति

जोहानिसबर्ग (10 सितंबर)रू इंसानों की नई प्रजाति ढूंढने का दावा किया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से लगभग 50 किमी दूर श्राइनिंग स्टारश गुफाओं में दफन 15 नर कंकालों के अधूरे हिस्से मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इनकी लंबाई 5 फीट और वजन 45 किलो से ज्यादा है।

साइंस मैगजीन ईलाइफश की रिपोर्ट से पता चलता है कि खोजी गई नई प्रजाति धार्मिक अनुष्ठान करने में सक्षम थी। अब दावा किया जा रहा है कि यह खोज इंसानों के पूर्वज को लेकर हमारी सोच बदलकर रख देगी। नई प्रजाति को श्होमो नलेडीश नाम दिया गया है। स्थानीय भाषा में इसका मतलब श्स्टार मैनश होता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, नलेडी का दिमाग काफी छोटा है। लगभग एक औसत संतरे के आकार जितना। खोजकर्ताओं की टीम का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर ली बर्गर ने बीबीसी को बताया कि उनका मानना है कि नई प्रजाति श्जीनियस होमोश यानी आधुनिक इंसान जैसी हो सकती है। उनके अनुमान के मुताबिक, यह प्रजाति 30 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती होगी।

http://hindi.news24online.com/homo-naledi-human-relative-species-81/

## पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, हमें लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

# आरक्षण से लाभ या हानि

**डॉ. उदित राज**
संसद सदस्य (लोक सभा)
राष्ट्रीय चेयरमैन,
अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का
अखिल भारतीय परिसंघ

गुजरात की पटेल जाति के द्वारा जो आंदोलन अभी हुआ उससे देश हिल गया। आरक्षण पर लगभग सभी विचार किए, चाहे पक्ष में या विपक्ष में। समय-समय पर यह विषय विवाद में आता रहता है। कुछ लोग राजनैतिक हथियार के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे जाति को इकट्ठा करना आसान हो जाता है। जो बेरोजगार हैं, उन्हें लगता है कि आरक्षण की वजह से ऐसी स्थिति में हैं। जातीय पूर्वाग्रह तो एक कारण है ही। अगर समाज और देश हित में आरक्षण नहीं है तो खत्म हो जाना चाहिए, यदि है तो विवाद किस बात का ?

आज़ाद भारत के पहले परिस्थितियां भिन्न रहीं। बहुतों की चिंता राजनैतिक आज़ादी की रही तो कुछ की चिंता समाज में मान-सम्मान की रही है। देश में तमाम ऐसी सोच रखने वालों में से एक डॉ0 अम्बेडकर भी रहे। उन्हें तथा उनके समर्थकों को लगा कि आज़ाद भारत में हमारी दशा क्या होगी। उस समय शासक अंग्रेज थे, जातीय भेदभाव और सोच से वे परिचित नहीं थे। उस समय दलितों और आदिवासियों की भागीदारी हर क्षेत्र में नगण्य थी। जब साइमन कमीशन भारत की समस्याओं के ऊपर अध्ययन करने आया तो यहां के दलितों को मौका मिला कि वे अपनी बात को रख सकें। परिणाम यह हुआ कि लंदन की गोलमेज सभा में बात उठी और 1932 में गांधीजी और बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का सोचना है कि इससे हिन्दू समाज की एकता बरकरार रह सकी वरना टूट भी सकती थी, क्योंकि दलितों को पृथक मताधिकार का अधिकार बर्तानी हुकूमत ने मंजूर कर ली थी।

शासन-प्रशासन में दलितों व आदिवासियों का आरक्षण इसके पहले कभी नहीं था, आरक्षण विरोधी बताएं कि तब देश गुलाम क्यों हुआ ? क्या यह कारण नहीं रहा होगा कि देश इसकी वजह से भी गुलाम हुआ होगा। इतनी बड़ी आबादी को अलग-थलग रखकर दुश्मन का मुकाबला कठिन तो था ही, कृषि, उद्योग एवं कारोबार पर भी असर पड़ा। जब इनके पास क्रयशक्ति नहीं थी तो अर्थव्यवस्था का तो कमजोर होना ही था। समाज में खटास की वजह से सुख-शांति पर असर तो पड़ना अनिवार्य था। यदि भागीदारी हुई होती तो ये अप्रत्याशित नुकसान समाज का न हुआ होता। आरक्षण के बाद और पहले के भारत की तुलना की जाए तो पता लगेगा कि बाद वाला बहुत अच्छा है और उसमें आरक्षण का योगदान बहुत है। आरक्षण की वजह से जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, उनका उत्पादन में योगदान एवं शासन-प्रशासन में हुआ। कपड़ा, खाना और तमाम उपभोग की वस्तुओं की क्रय-शक्ति बढ़ी और इसका असर औद्योगिक उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर पड़ा। दलितों और पिछड़ों में राष्ट्रीयता का बोध हुआ। जब ये केवल मजदूर और अछूत थे तो वैसी स्थिति में राष्ट्रबोध का ज्ञान कैसे होता? यहां वह चौपाई बहुत सांदर्भिक है - "कोउ नृप होई हमहि का हानी , चेरि छाणि अब होब का रानी।" इसका मतलब है कि राजा कोई भी हो, वंचित को क्या फर्क पड़ता है।

जो लोग योग्यता और दक्षता की बात करते हैं तो उन्हें हाल में हुए व्यापक अध्ययन के निष्कर्ष को जान लेना चाहिए। अश्विनी देशपांडे, प्रोफेसर - दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स एवं थामस विसकोफ, प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) - मिसिगन विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति एवं जन जातियों को आरक्षण देने के कारण भारतीय रेलवे में 1980 एवं 2002 की अवधि का अध्ययन किया, जिसकी रिपोर्ट 'वर्ल्ड डेवलपमेंट जोर्नल' में छपी। भारतीय रेलवे पूरे विश्व में सबसे बड़ा नियोजक (नौकरी देने वाला) है, जहां पर आरक्षण लागू है। रेलवे में ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक में मिलाकर लगभग 13 से 14 लाख लोग काम करते हैं। 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों एवं 7.5 प्रतिशत जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण लागू है। इस अध्ययन ने पाया कि ग्रुप ए एवं बी के अधिकारी आरक्षण के कारण ही इन पदों पर पहुंच सकें हैं। प्रो0 देशपांडे एवं प्रो0 विसकोफ ने उन जोनों की तुलना की जिनमें ज्यादा दलित कर्मचारी अधिक कार्यरत् थे और जिनमें कम कार्यरत् थे। उन्होंने पाया कि दोनो जोनों में कार्यक्षमता और उत्पादकता में कोई अंतर नहीं है, उल्टे उन्होंने पाया कि कुछ जोन जिनमें दलित कर्मचारी ज्यादा थे, वहां ज्यादा उत्पादकता हुई है।

आरक्षण के बावजूद प्रमुख स्थानों पर अनारक्षित वर्ग के ही लोग बैठे हैं। लगभग सभी विश्वविद्यालय, आईआईटी एवं उच्च संस्थानों में प्रोफेसर या अहम पोस्ट पर अनारक्षित लोग ही बैठे हैं, तो हमारे देश में शोध और तकनीकी विकास क्यों नहीं हो पाया ? हाल में अमरीका के चार राज्यों का दौरा किया और सैकड़ों भारतीय डॉक्टरों से मुलाकात हुई। चर्चा के उपरांत बात उभरकर आयी कि भारत में एक भी जेनेरिक दवा की खोज नहीं हुई है। क्या इसके लिए आरक्षण जिम्मेदार है? सेंटर ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की ओर से जारी 1,000 शीर्ष यूनिवर्सिटी की सूची में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार तीसरे साल पहले पायदान पर रखा गया है। भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी शीर्ष 300 में भी शामिल नहीं है। आई.आई.टी. संस्थानों के पास तो सुविधाएं एवं पैसे की कमी नहीं है, तो फिर क्यों नहीं एक भी मौलिक रिसर्च कर पाए? उच्च न्यायपालिका में दलित व पिछड़े तो नहीं के बराबर हैं, फिर क्यों मुकदमें के फैसले में विलंब और बार-बार भ्रष्टाचार की बात उठती है। हाल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में 50 प्रतिशत जज भ्रष्ट हैं। यही बात वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिभूषण भी कह चुके हैं । दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह ने कहा कि 94 प्रतिशत मृत्यु दंड दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को ही दिया जाता है। भारत सरकार में लगभग 150 सचिव हैं - एक या दो को छोड़कर सारे अनारक्षित वर्ग से हैं तो क्यों विभागों में शिथिलता, भ्रष्टाचार और पक्षपात है? क्या इन सब चीजों के लिए आरक्षण जितम्मेदार है ?

जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उनको भी इसका परोक्ष लाभ मिल रहा है। ज्यादातर शिक्षण संस्थाएं, उद्योग, कारोबार तथाकथित सवर्णों के लिए आरक्षित वर्ग के लोग इनका उपभोग करके किसका मुनाफा बढ़ाते हैं? तमाम सवर्णों की शिक्षण संस्थाएं आरक्षित वर्ग के छात्रों से चलती हैं, क्योंकि ये सीट भरने में सहयोगी तो होते हैं, साथ-साथ जो छात्रवृत्ति सरकार से मिलती है, सीधे इनका फायदा होता है। जब तक मंडल लागू नहीं हुआ तब तक 10 से 15 प्रतिशत तक ही सीटें पर आरक्षित वर्ग के लोग थे। तब सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार व विलंबता की नींव क्यों पड़ी? जिन्हें आरक्षण दिया है, वे देशवासी हैं, शत्रु नहीं, तो यह विरोध क्यों ? गुजरात में पटेल समाज के जो नवजवान आंदोलन कर रहे हैं, उनका आक्रोश है कि अपनी ही जाति के उन्नति किए लोगों से वे पीछे रह गए हैं। दुनिया की कोई भी जाति हो उसमें शत्प्रतिशत् मालामाल नहीं होते। दूसरा कारण कि सरकारी नौकरी का आकर्षण, यदि आरक्षण समाप्त भी कर दिया जाए तो सवर्णों के सभी पढ़े-लिखे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। एक तरह से इनका आंदोलन आरक्षण विरोधी है। किसी भी दृष्टि से मूल्यांकन कर लिया जाए तो पाया जाएगा कि आरक्षण से देश और समाज का लाभ ही लाभ है, नुकसान किसी तरह से नहीं है।

+++

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का
**अखिल भारतीय परिसंघ**
के राष्ट्रीय अध्यक्ष
**डॉ0 उदित राज के आगामी कार्यक्रम**

18 सितंबर, 2015, सायं 10 बजे
न्यू सर्किट हाउस, रायपुर, छत्तीसगढ़
सम्पर्क : अनिल मेश्राम, मो. 9893008233,

19 सितंबर, 2015, सायं 5 बजे
राजमिलन वेंकट हाल,
बिजनौर, उत्तर प्रदेश
सम्पर्क : वेद प्रकाश, मो. 09412361352
एवं महावीर सिंह, मो. 9412489918

20 सितंबर, 2015
अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र, कंकड़ खेड़ा, मेरठ
सम्पर्क : इं. प्रेमजीत सिंह, मो. 9219279599

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का
**अखिल भारतीय परिसंघ**
द्वारा रेलवे कर्मचारियों का सम्मेलन 27 सितंबर को मावलंकर हाल, दिल्ली में

पूरे देश में अनुसूचित जाति/जन जाति की एसेसिएशन एवं संस्थाएं कर्मचारियों-अधिकारियों द्वारा बनायी गई हैं लेकिन उनके द्वारा अपेक्षित रचनामत्क कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली में बैठ कर रेलवे कर्मचारियों का चंदा खा रहे है और दलित आंदोलन को बेच रहे है। न तो उचित ट्रांस्फर-पोस्टिंग हो रही है और न ही भर्ती हो रही है। ऑल इंडिया एस.सी./एस.टी. इम्प्लाइज एसोसिएशन द्वारा रेलवे के कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। यदि कोई कर्मचारी आवाज उठाता है तो उसे डरा- धमका कर उसके पद से हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर अपनी मर्जी का व्यक्ति बैठा दिया जाता है। रेलवे एस.सी./एस.टी एसोशिएन में अपनी बात कहने की भी अज़ादी नही है इसलिए ऐसे लोगों को बदला जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए परिसंघ द्वारा डॉ0 उदित राज जी के नेतृत्व में 27 सितम्बर 2015 को प्रातः10 बजे से मालवंकर हाल, कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में सेमिनार किया जाएगा जिसमें देश के सभी रेलवे कर्मचारी-अधिकारी व वेलफेअर एसोशिएन के सदस्य एवं पदाधिकारियों को अमंत्रित किया जा रहा है। सेमिनार का उद्देश्य रेलवे एस.सी./एस.टी कर्मचारियों के भविष्य की योजनओं पर चितंन तथा रेलवे एसोसिएशन को कर्मचारियों हित में प्रभावी बनाना है।
संपर्क : ब्रह्म प्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव, मो. 9871170028

# Does Reservation reduce productivity? The case of Indian Railways

**Ashwini Deshpande**
Delhi School of Economics
ashwini@econdse.org

**Thomas Weisskopf**
University of Michigan
tomw@umich.edu

Critics of job reservations argue that such policies have an adverse effect on work efficiency and productivity. This column analyses the effect of job reservations in the Indian Railways – the world's largest employer subject to affirmative action. It finds that having a larger proportion of lower-caste employees is not associated with lower productivity; in top-tier jobs, in some cases, it is actually associated with higher productivity.

Affirmative action (AA) encompasses public policy measures designed to reduce the marginalisation of members of groups that have historically suffered discrimination, exclusion, or worse. India has not only the longest history of AA policies but also the most comprehensive system of AA, reaching far more people than all such policies elsewhere in the world. The most prominent form of AA is 'reservations' or quotas for the Scheduled Castes (SCs) or Dalits, and the Scheduled Tribes (STs) or Adivasis. Together, 22.5% of all seats in central-government-supported higher educational institutions, public sector jobs and elected positions are reserved for these groups.

Criticism of AA policies in India is much the same as in most other countries where such policies have been implemented. It is argued that these policies conflict with considerations of merit because less qualified candidates are selected in place of more qualified candidates, and hence, poorer academic performance and poorer quality of work on the job is to be expected from AA beneficiaries. Some critics have even suggested that the failure to allocate key jobs on a strictly meritocratic basis has resulted in serious injuries, as well as gross inefficiency. For example, in "Job Reservation in Railways and Accidents," (Indian Express, September 1990), it is charged that the frequency of Indian railway accidents would likely increase because reservation policies result in a larger proportion of less competent railway officials and lower overall staff morale. But advocates of AA – in India and elsewhere – argue that hiring is otherwise often far from truly meritocratic, and that workforce diversity may actually generate efficiency gains as individuals from diverse backgrounds bring complementary skills to an organisation.

**Assessing effects of affirmative action on efficiency in Indian Railways**

To shed light on this debate, we focus on the world's largest employer subject to AA – the Indian Railways (IR), with roughly a million and a half employees – in an effort to assess the effects of job reservations for SC/ STs on productive efficiency. In the United States, where AA in hiring has been practiced in many industries since the 1960s, a variety of studies of this kind have been carried out. In developing countries, however, such studies are very few in number. The only studies assessing the impact of AA in India focus either on electoral representation, or on higher education. To our knowledge there has not yet been any systematic quantitative study of the effect of job quotas on enterprise efficiency.

For our study of the IR, we first compiled data from various annual reports on productive inputs (labour, capital and fuels) and outputs (passenger kilometers, and freight tonne kilometers), distinguishing SC/ ST employees from non-SC/ST employees at different job levels, for eight regional railway zones from 1980 through 2002. Using the employment data we then constructed variables representing the SC/ ST percentage of IR employees (SCST%), first for all employees and then for high-level employees only. The Indian Railways, like all departments of the government, hire workers in four different labour categories: categories A and B are the top two tiers of employees, comprising administrative officers and professional workers; category C includes semi-skilled and clerical staff; and category D includes relatively unskilled attendants, peons and cleaning staff. We consider the SCST% in A+B category jobs to be the better indicator of the effect of AA on IR operations, because almost all SC/ ST employees in high-level positions are AA beneficiaries – they would not have been able to reach such positions in the absence of India's reservation policies.

Our approach to analysing the effect of reservations on productivity in the IR is as follows. Using two different econometric techniques – production function analysis and data envelopment analysis - we estimate total factor productivity (TFP) for each zone in each year; and then, in a number of ways, we assess whether the proportion of reserved category employees (in total, and in high-level jobs) could possibly account for the variation in productivity across zones and across years.

**Greater proportion of lower-caste employees in top-tier jobs improves efficiency, in some cases**

Our analysis of an extensive dataset on the operations of the IR provides no evidence whatsoever to support the claim of critics of AA that increasing the proportion of AA beneficiaries adversely affects productivity or productivity growth. On the contrary, some of the results of our analysis suggest that the proportion of SC/ ST employees in high-level positions (at the A and B job levels) is positively associated with IR productivity and productivity growth.

Our finding of such positive associations in the case of SC/ ST employees in A and B jobs is especially relevant to debates about the effects of AA, for two reasons. First, the efficacy with which high-level managerial and decision-making jobs are carried out is likely to have a considerably bigger impact on overall productivity than the efficacy with which lower-level semi-skilled and unskilled jobs are fulfilled. Thus, critics of AA are likely to be much more concerned about the potentially adverse effects of favouring SC/ ST candidates for A and B jobs than for C and D jobs. Second, it is precisely in the A and B jobs – far more than in C and D jobs – that reservations have been indispensable for raising the proportion of SC/ ST employees. Even without reservations, one would expect substantial numbers of SC/ ST applicants to be hired into C and D jobs; but without reservations very few SC/ ST applicants would have been able to attain jobs at the A and B level.

Our results are consistent with those of productivity studies in the United States. In a survey of US research in this area, Holzer and Neumark (2000) concluded: "There is some evidence of lower qualifications for minorities hired under affirmative action programs…" but "Evidence of lower performance among these minorities appears much less consistently or convincingly…". Our results for the IR are stronger, however, in that we do find some suggestive evidence that AA at the upper levels of the job market may actually contribute to greater productivity.

How could AA have this effect? One possible reason is job market discrimination: hiring practices are often far from meritocratic in the absence of AA; the capabilities of applicants from the lower castes are not fully recognised. Indeed, in a study of the highly-skilled private sector job market in the modern, urban Indian context (often assumed to be among the most meritocratic), Deshpande and Newman (2007) show how caste and religious affiliations of job applicants shape employers' beliefs about their intrinsic merit. This confirms the findings of other studies that uncover how employers discriminate in job markets based on social identities, and that hiring and salary offers are not always made based on merit, or 'what you know', but on social identities, networks, and 'who you know' (for instance, Bertrand and Mullainathan 2004, Pager and Western 2005, Thorat and Attewell 2007, Siddique 2008, Jodhka and Newman 2007). Thus, AA can redress the negative effects of discrimination.

Our findings of an improvement in economic performance due to AA can also be explained in other ways. Individuals from marginalised groups may well be highly motivated to perform well when they attain decision-making and managerial positions, because of the fact that they have reached these positions in the face of claims that they are not sufficiently capable, and they may consequently have a strong desire to prove their detractors wrong. Or such individuals may simply believe that they have to work doubly hard to prove that they are just as good as their peers, so they may actually work harder. To have greater numbers of managers and professionals from disadvantaged groups working in high-level positions might increase productivity because their backgrounds make them more effective in supervising and motivating other workers from their own communities. Finally, as Page (2007) has shown, improvements in organisational productivity may result from the greater diversity of talents and perspectives made possible by the integration of more members of marginalised groups into high-level decision-making teams.

http://www.ideasforindia.in/article.aspx?article_id=402

✦✦✦

(Contd. from page 7)

## Regional/Zonal Meeting of All India Confederation of SC/ST Organization in ...

promotions in 2012 which we were able to save in 2006.

All the Dalit employees should understand and use the Confederation as platform for their fight and struggle for justice.All the retired employees association should also work to strengthen the Confederation.Confederation can function like a pressure force for quick results. Everyone should try to bring in more members to join the confederation.For our goals we need Confederation.If Confederation is strong then all members are strong.Unity is important. RSS is a good example of dedication & unity. Contribute through sincere dedication.Educate others and give time for the society.

We also need Cadre camp for the members.Reservation is not poverty removal program.Dalit employee or officer are not obstacles & are not in the way of the development of the country.Gender equality, gender main streaming, networking, leaderships, financial freedom is the essential aspects of women empowerment. Dr. Ambedkar realized this at his time and included in the process of social reforms.

We should learn about women empowerment, development & progress from the foreign countries like Australia, America, Norway and Canada etc. It is important to be there in Parliament. Please strengthen my hands. People worship the powerful and strongest. You all members of the confederation are my strength and force. When we all are one and together then I can work for the betterment of everyone. Jai Bheem!

- **Dr. Anju Kajal**
Gen. Secy, Delhi Pradesh
SC/ST Confederation

# RESERVATION – PROFIT OR LOSS ?

**Dr. Udit Raj**
Member of Parliament (Lok Sabha)
National Chairman
All India Confederation of
SC/ST Organizations

The Patel community of Gujarat has virtually shaken the nation. All sorts of opinions were expressed on the issue of reservation – for and against. This issue is debated from time to time. Some people use it as a political weapon as it makes it easy to unite people on caste grounds. Unemployed realize their plight is because of reservation. Caste anticipation is one reason. If reservation is not in favour of community and the country, it should go. Then there remains no dispute.

Circumstances were different pre-Independence. Some people craved for political independence while others for self-dignity and self-respect. Dr. B.R. Ambedkar was one of such thinkers who craved for self-respect. He and his supporters thought of our plight in independent India. The English were the rulers then. They were ignorant about caste discrimination and caste considerations. Participation of Dalits in all walks of life was negligible. However, when the Simon Commission came to India to study the problems faced by its people, then the Dalits got an opportunity to say their version of things. As a result the issue was raised at the Round Table Conference in England and an agreement was reached in 1932 between Gandhi ji and Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar which is known as the Poona Pact. Some people think that it could maintain unity amongst the Hindus which could even break because the British monarchy had approved the right to separate vote by the Dalits.

Before this there was no reservation for the Dalits and Adivasis. Anti-reservationists may tell why the country became a slave then? Is it not so that the country would have become a slave only because of reservation? It was but natural that by keeping such a large segment of society apart, it was difficult to tackle the enemy. It also adversely affected agriculture, industry and business in India. When the people did not have the purchasing power, the economy was bound to weaken. Sourness in the community did affect people's peace of mind. Had there been participation of Dalits in the mainstream of society, the Samaj would not have suffered such an unprecedented loss. If we compare pre-reservation India and post-reservation India, we will find the latter is extremely good and reservation has major role to play in it. Our buying power for clothes, food and all other consumable goods has increased and it has, in turn, impacted the industrial production and the economy. Dalits and backwards have realized the spirit of nationalism. When they were only labourers and untouchables how could they realize nationalism? There is a maxim whosoever may be the King, it does not make any difference to the poor.

People who talk of ability and efficiency should know of the findings of a recent study. Prof. Ashwini Deshpande of Delhi School of Economics and Prof. of Economics Thomas Viskof of Michigan University conducted a joint study giving cases of reservation in the Indian Railways between 1980 and 2002, findings of which were published in the World Development Journal. The Indian Railways is the biggest employer in the world where reservation is applicable. Around 13 to 14 lakh people work in the Railways from Group A to Group D. There is 15% reservation for scheduled castes and 7.5% for scheduled tribes. Besides this, there is reservation for backward classes. This study revealed that Group A and Group B officers could reach at this level only because of reservation. Prof Deshpande and Prof Viskof studied both the zones having the maximum and the minimum number of Dalit employees. They found that there was no difference in the quantum of efficiency and production of both the zones. On the contrary, they found that the zones having more Dalit employees showed more production.

Despite reservation, important posts are occupied by the unreserved categories in Universities, IITs and other important places; even then there is no progress in research work and technology. I recently visited four States of the U.S.A. and interacted with hundreds of doctors. After discussion it came out that India could not find out even a single generic medicine. Is reservation responsible for that? Harvard University of the USA is placed at the first place for the last three consecutive years amongst one thousand top universities by the Centre of World University Rankings. No Indian University is amongst the 300 top universities. IITs do not have any dearth of resources and money. Even then why none could do even a single fundamental research. Only negligible number of Dalits is there in higher judiciary. Even then why there is delay in deciding the cases and why corruption crops up? Recently former judge of the Hon'ble Supreme Court of India has said that half of the judiciary has corrupt judges. Senior advocate Shri Shanti Bhushan has also expressed identical views. Former Chief Justice of the Delhi High Court Shri A.P. Shah has said that 94% of capital punishment is imposed on the Dalits, minorities and backward classes. There are around 150 Secretaries in Government of India – barring one or two all come of unreserved categories. Then why there is slackness, corruption and nepotism in Government departments? People opposing reservation are also drawing direct benefits from it. Who is being profited by utilizing services provided by educational institutions, industry, business and reserved category of so-called Savarnas? All educational institutions being run by the upper caste people are directly benefited by reserved category students as they help in filling up the reserved category seats and also help in procuring Government scholarships. Reserved categories occupied only 10 to 15 percent of the seats till Mandal Commission gave its recommendations. Then why foundation of corruption and delay was laid in Government departments? People who are given reservation are also citizens of this country, not our enemies. Then why this opposition? The youth of Patel community of Gujarat complain that they have lagged behind their own community people. No community in the world ever becomes wealthy cent per cent. The other reason is the attraction towards Government jobs. Even if reservation is stopped, all educated people of the Savarnas cannot be given Government jobs. In other words, their campaign is anti-reservation. In a nutshell, we find that the country has benefited from reservation if we evaluate the prevailing situation from any angle. Nobody is the loser.

✦✦✦

# Regional/Zonal Meeting of All India Confederation of SC/ST Organization in Allahabad & Kanpur, UP

Meeting was held at VigyanParishad Auditorium, Paryag, Allahabad on 5th of September 2015 and Chhatrapati Shahuji Maharaj University auditorium, Kanpur on 6th of September 2015.

UP State employees who are member & affiliated to All India Confederation of SC/ST Organization chaired by Honorable Member of Parliament Dr. Udit Raj gathered to discuss the removal of reservation in promotions by the UP government and the effects of demotions because of the same.

Dr. Anju General Secretary, Delhi Unit & member of the National Executivebody was also present along with Dr. Udit Raj to give a boost to the youth wing and increase the member drive of ladies employees (women empowerment).

During the meeting all the concerning issues were raised and the future course of action was discussed. Reservation is on the verge of being abolished. People should know about their rights, about reservation and should show interest and keep track of latest developments. Involvement is necessary. 30% reservation stopped, demotions of employees in UP are some examples people should see.The current status of the 85th amendment in the UP State was explained and people were informed that the reservation that we got in 2001 in the form of 85th amendment has been taken back in 2012. It is our Confederation that will fight for this and will use all efforts to restore the respect and the promotion back provided we all fight for it as a unit and create mass movement to pressurize the government.

Confederation is committed to stop the demotions that's happening in UP. People should come out of illusion, face the reality and support their Confederation. They should revolutionize the demand for reservation which is their right as per the Indian constitution.All the working Dalit members should come together as one unit and create a background for a larger movement to protect our own rights. All have to come out together to fight for reservation else they will not be able to enjoy the benefit of it in near future.Privatization is happening all around. Therefore, we will not have any job reservations left in the government.All the serving/working Dalit members & officers who have used and enjoyed the quota of reservation should payback to society and should help more fellow Dalit brothers and sisters for their better future.

Members should learn to return back and also give time from their own personal life. Else you will not get anything. Think that what your ancestors could not get, you got it because of Baba sahib then why there is hesitation to payback to society for the betterment of your own fellow members.Baba Sahib had visualized this long back and therefore fought for reservation. What you have received is not free but it's the result of the sacrifices, struggle, time and efforts of Baba sahib. Therefore, one should contribute financially and socially to strengthen the Confederation. We need to get in touch and establish connection with all the missions (using Dr. BR Ambedkar) and make them to work together and if possible under one umbrella.

Please note that even after when they are well to do other cast like Patels, Jats, Gujjars etc. are also demanding reservations. They are coming out on roads in the form of a big movement.Everyone should try to understand the politics and should avoid disliking it. We can achieve a lot through politics if we can stand united.In our country labor force is not doing any mass movement to demand a change; instead it is the rich who are doing it. In foreign countries it's the labor force that's in the front for demanding change in system.

Confederation is also committed & working towards reservation in judiciary. The other highlight is that today's media is paid media. Dalit exploitation is not shown and you don't see the atrocities that are happening on Dalit's across various parts of India. Whereas, you see high profile murder cases from morning to evening every day.Therefore, social media is one of the strongest modes of communication. It is like a bomb, fire. What you say can reach millions very fast. Therefore, everyone should try and connect using WhatsApp, FB etc.

All the organizations, NGOs, missions under the name of Dr. BR Ambedkar have to join hands and have to show unity to become a big force that can be seen. I appeal to the enlightened people to come out of their houses and participate to show solidarity in favor of reservation like in Gujrat episode where all the anti-reservation forces gathered whose main demand was abolishing the reservation. In short, the reality behind the Gujrat movement was to end all the reservations.

Importance is being given to sub casteism within Dalits and I am totally against it.We should also try to expose members who are trying to divide us within Confederation. It's because of these we have lost the reservation in

(Contd. on page 6)

# VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 20 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 September, 2015

# EXTRA CONSTITUTIONAL JUDICIARY

**Dr. Udit Raj**
Member of Parliament (Lok Sabha)
National Chairman
All India Confederation of
SC/ST Organizations

India is the largest democracy in the world. Most of the countries of the world have democratic set up of governance. There is no need of police Bandobast, no fear of musclemen and no use of black money whenever there are elections. Any Government official may conduct elections without any fear of rigging. There is no provision of judges electing judges in such countries. When no judge can appoint a judge in developed countries, it should not be done in India as well. We should advance towards maturity. In the present era there is hardly any other issue as important as the appointment of judges in judiciary. Under the 99th Constitutional Amendment, National Judicial Appointments Commission was constituted so that justice is done to everybody and capable persons are appointed as judges. Twenty states did give their consent to this Amendment. It may not be presumed that all political parties have united against the judiciary. The inner voice of the people made them to do so lest they should not unite. There should not have been any dispute thereafter but litigation started. It is argued that it would have greater impact on political influence. Since Independence till 1998, the executive had greater role to play in appointments. People have started reminiscing about the old system saying that it was a better system. That system had declared election of Indira Gandhi as null and void and the common man did not have to pay much as court fee. Today he cannot pay the fee of experienced lawyers even by selling his entire self. National Judicial Commission will have six judges headed by the Chief Justice of India. It would include two judges, Law Minister and two prominent citizens. Some people say it would increase political influence. In no other democratic country of the world judges appoint judges. This unique arrangement is only in India. When attempt was made to balance this system, some people with vested interests raised another debate. As in other countries, judges should not have any role in their own appointments. Such situation should be probed impartially.

In the United States of America, the Senate Committee selects the names of judges and for some days these names are debated amongst the public through various media. So such intense discussion is held that hardly any aspect of individual's personal life remains untouched. After that the American Senate approves these names. In Russia half of the judges are nominated by the President and the rest are elected directly by the people. Therefore, there is no chance of favouritism or nepotism. Article 124 of the Constitution of India also provides that the executive will have the lead role in appointment of judges. This right has been encroached upon by the judiciary through its own decision and since 1998 judges started making appointments of judges. People did not oppose this move. But with the passage of time people started becoming restive. The matter is simmering fire in people's hearts and minds as no one can criticize judges. It is but natural that we make friends and foes through our continued interaction with each other right from becoming advocates to becoming judges. Therefore, it should be incumbent upon judges that they should have no role in appointment of judges. Despite this hard fact, the National Judicial Commission has three judges.

Shri A.P. Shah, former judge of the Delhi High Court once said death penalty is meant only for the poor and Dalits. As per available data, the poor gets the maximum death penalty. The first senior advocate Indira Jaisingh filed a Public Interest Litigation to say that there must be some yardstick to make senior advocate. In the PIL it is submitted that only one Dalit and two backwards could become senior advocates so far. It is not difficult to understand the quantum of discrimination involved. In the PIL it is also alleged that the advocates who are proficient in human rights, international law, family law and special subjects like distribution of inter-State river waters, cyber law, etc., are not made senior advocates. The Attorney General of India, Shri Mukul Rohtagi has rightly reasoned that National Judicial Commission may not make any difference in the federal structure of India. He said it would not affect self-reliance of the executive. It is only after a judge starts working after his selection that the question arises whether interference is made in his working, or not, which is not the fact. He has further reasoned that there were some judges of the High Courts who could not dispose of even one hundred cases during their entire life span and even then they were elevated as Supreme Court judges and thousands of litigants got stranded in the High Court. There is another kind of judges who hear cases from 11am to 12 noon, or 3pm to 4pm. In such a situation it is but natural that crores of cases would keep piling up. Is it the failure of the Collegiums system? The Parliament has got the right to devise ways and means to elect judges.

It is ludicrous that Supreme Court judges gave reasoning while giving verdict against the National Judicial Commission that it would impede the way for Dalits and women into the judiciary. Had the Collegiums made women and Dalits as judges then the Collegiums system would have been held suitable in judiciary? One renowned advocate argued that the Members of Parliament do not have any understanding of the National Judicial Commission. As per his philosophy all the MPs are a foolish lot. To uphold impartiality the Supreme Court Bar Association maintained that there should not be any role of advocates in the appointment of judges. It appears as if this famous advocate could be the father of Indian Penal Code, CRPC, Indian Evidence Act, Jurisprudence, etc. and the elected MPs have a very low IQ. In other words, this very advocate meant that all the public is foolish because it is the public who elect MPs. Whatever the qualifications of an MP may be, we should not forget that he represents intelligence of the public. Only our country gives so much freedom of right to speech. It was even said that 2G spectrum accused are also intelligent citizens and they may also participate in the National Judicial Commission. It would be better if judges were appointed on the pattern of developed countries. Because of their prime role in the executive they would be held accountable to the people. The National Judicial Commission would bring about a sea of change in the judiciary; crores of pending cases would be disposed off expeditiously and the public would be able to plead their cases before the higher judiciary.

+++

## All India Confederation of SC/ST Organizations

## NATIONAL RALLY TO BE AT NEW DELHI ON 07th DEC 2015

**Friends, the movement to end reservations has been started by the Patel community leader, Hardik Patel by holding a rally of 5 lac people. Patels are amongst the richest communities of the country. We should not hold the misconception that no one can end reservations. Earlier, we used to say that reservations cannot be finished, but today around 40% reservations have been abolished by the Government. What have we done about it? The recruitment of Class IV staff has been completely stopped, now class IV staff are either outsourced or appointed on ad-hoc basis. We have not able to pass the Bill for reservation in promotions. In Uttar Pradesh, even demotions have started. If we want to save reservations, we must hold a rally of 10 lac people. That s why I am requesting you to attend in very large numbers the rally being held by the All India Confederation of SC/ST Organizations on 7th December 2015 at 10 am at Ramlila Maidan, New Delhi. Send me through mail or whatsapp names and numbers of lakhs of missionaries. I want to talk to them to make the rally successful. Our whatsapp number is 9999504477 and email is parisangh1997@gmail.com.**

**- Dr. Udit Raj, National Chairman**

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar

# भगवान बुध्द और पवित्र महाबोधीवृक्ष

विश्वकल्याण के विश्वगुरू भ.बुध्द है। उन्होने विश्व के लिए शांती,प्रेम,सत्य,अहिंसा,प्रज्ञा,शील, करूणा,दया और मानतावाद उन महान तत्वो का उदघोष किया। उन्होने विश्वकल्याण के लिए और सत्य की खोज के लिये अपना गृहत्याग किया।उनका जनम लुंबिनी मे (इ.स.पू. 563 ते 483)हुआ। बाद मे वो सत्य और ग्यान की खोज के लिये वो घुमते रहै। उससमय बिहार नजीक बन मे वो आये तब उन्है निरंजना नदी के पास उरूवेला बन मे पिपल वृक्ष के निचे अंतीम अवस्था प्राप्त हुई और ग्यान हुआ। और वो सम्यक सम्बुध्द हुये।बुध्द ये कोई जात या पात नही बल्की ये एक महान तत्वग्यान है।भ. बुध्द ये नाम बिहार की गया को प्राप्त हुआ।इसी वजह पिपलवृक्ष भी बोधी वृक्ष बन गया।

वैदिक संस्कृती मे पिपलवृक्ष को भगवान माना गया।गीता मे श्रीकृष्ण खुद को अश्वत्थ कहथो थो।अश्वत्था याने पिपल,पदमपुराण मे कहा गया।जो भी कोई पिपल वृक्ष पुजा करता उन्हे अंतीम अवस्था ग्यान प्राप्त होता।सिंधू संस्कृती ये वैदिक संस्कृती से पहिले है।सिंधू संस्कृती ये नागवंशी भारतवासियो की मुल संस्कृती है। सिंधू संस्कृती मे पिपल वृक्ष के तस्वीरे मिली थी।बुध्द धम्म के इतिहास के अनुसार 24 बुध्द पहिले हो चुके है। ऐसा सम्राट अशोक का शिलालेख कहता है। उनमे से पहिले दिपंकर और चार बुध्द पिपलवृक्ष के निचे ग्यान प्राप्त करने के लिये बैठते थे ।

भा.बुददने द्वेष,नफरत,लोभ,काम,आकर्षण,इन सभी पर विजय प्राप्त किया।उन्होने स्वतंयिं,समानता,भाईचारा,न्याय ये तत्वे लोगोको बताये।नस्लीय भेदभाव,जातीभेद अस्वीकृत करके सभीको समानता बताई।मानवतावाद बताया।भ.बुध्दने ये ग्यान पिपल के पेड के निचे प्राप्त किया इसलिये पिपल के पेड को बोधीवृक्ष कह जाता है।पिपल के पेड को अंग्रेजी मे 'बोट्री' और पाली भाषा मे 'पिप्पळ',महाबोधी ऐसा कह जाता है।जिस दिन सिध्दार्थ का जनम हुआ उसी दिन बोधीवृक्ष का भी हुआ। महान 'अट्ठकथाकार आचार्य बुध्दघोष ' उन्होने ऐसा कहा है की,सात सप्ताह भ.बुध्द बोधीवृक्ष के निचे बैठते थे।उन्होने ऐसी प्रतिज्ञा की आकाश मे से चॉंद और सुरज टूटे या पहाड या सागर गायब हो मै जनहित के लिये ग्यान प्राप्त किये बिना उठूंगा नही। उसी वजह से बोधीवृक्ष का महत्तव और बढा। वो और भी वंदनीय हुआ।भ. बुध्द पिपल के पेड के निचे सात सप्ताह बैठेते। उसके बाद भ.बुध्द को ग्यान प्राप्त होने बाद सात दिन तक पलक हिले बिना एक नजर से बोधीवृक्ष को देखते रहै। भ.बुध्द स्वंय बोधीवृक्ष की पुजा की।भ.बुध्द ने अनेक दवाई की खोज की। उनका योगा ग्यान बहोत गहन था। उन्होने योगा का महत्तव लोगो को बताया। वो कहते थे की,जो ग्यान योगा करने से मिलता है वो योगा न करने से नष्ट हो जाता है । (धम्मपद 242) योग का दर्शन भ. बुध्द का मध्यम मार्ग मे मिलता है। योग यह परंपरा सिंधू संस्कृती मे से बौध्द एंव जैन के विचारधारा वो मे है।भ.बुध्द ने सबसे पहले अपना ध्यान बचपन मे जांभूल के पेड के निचे किया। दुसरा ध्यान उन्होने गृहत्याग के बाद मल्ल प्रदेश की राजधानी 'अनुपिया' यहॉ आम्रबन मे किया।और तिसरा ध्यान उन्हाने पिपल के पेड के निचे किया। और उन्होने ग्यान प्राप्त किया।1. ललित विस्तार 2.जातक अर्थकथाये उन ग्रंथो मे सुजाताने भ. बुध्द को खिरदान किया हुआ है ऐसा कहा।बोधीवृक्ष के निचे भ.बृध्द वज्रासन अवस्था मे बैठे, और मन ही मन सोचते रहै की,जो मुझे ग्यान प्राप्त हुआ है वो मै लोगो को दूँ की नही क्यूकी धम्म शांत और गंभीर है। समजने के लिये थोडा मुशकिल है। बुराई का नाश करनेवाला है।औरो को नही समझमे आया तो मेरा ये उपदेश निरोपयोगी होगा ऐसा उन्हे लगने लगा। परंतू उन्हे विश्व कल्याण के लिये अपना ये धम्म लोगो बताना जरूरी लगने लगा।जब जेतबन मे आनंद ने बोधीवृक्ष लगाया तब भ.बुध्द बोधीवृक्ष के निचे ध्यान लगाकर बैठे।उसके बाद उन्होने अपना पहला प्रवचन वाराणसी नजीक 'मृगदायबन' पाच भिक्षू को दिया।उन्होने बताया की विश्व मे दुःख है और कारण लोभ है।

पंचशिल और अंष्टागिक मार्ग उन्हाने बताये। उन्होने अपनी उमर के पैतालीस बरस विश्वकल्याण के लिये हिमालय से दक्षिण भारत तक धम्म का उदघोष किया लोगो को बताया।

सम्राट अशोक :यह बौध्द धम्म के सबसे अच्छे प्रचारक थे।उन्होने लुबिनी,सारनाथ, बुध्दगया, कपिलवस्तू, उन धार्मिक स्थलो सफर किया।राजा प्रसेनजित ने सबसे पहले बोधीवृक्ष के परिसर मे लकडे की दिवार खडी कि।ऐसा इतिहास संशोधक 'अलेक्झांडर कनिहॅम' कहते है की बाद मे सम्राट अशोक बोधीवृक्ष पास 20 फुट दिवार खडी कि।श्रीलंका देश मे सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा उन्होने धम्म का प्रचार किया। बोधीवृक्ष के सम्राट अशोक हररोज पुजा करते थे। उनकी युवा राणी तिष्यरक्षिता ये उनकी चौथी पत्नी थी। वो बहोत सुंदर थी। उन्हे लगता था की,राजा मेरी तरफ ठिक से ध्यान नही देते तो उन्होने बोधीवृक्ष की जलाया था।परंतू सम्राट अशोक ने हररोज दुध के भरे हुये कही घडे वहापर डालते थे। आगे बोधीवृक्ष फिरसे हराभरा हो गया। 'महावंश ' और 'दिव्यावदान' ये ग्रंथ बहोत उपयुक्त है।इ.स.न.के पहिले शतक मे शकराजा हुणवंतू (मिहीरकुल) उन्होने बोधीवृक्ष को तोडा। बंगाल के राजा शंशाक उन्होने कही बुध्दविहारे तोडी और बोधीवृक्ष को जलाया।और उसके जडे उखाडकर फेक दी। बाद मे मगध के राजा पुर्णवर्मण उन्होने बुध्दगया की धम्मयात्रा की।और बोधीवृक्ष के जडेपर कही घडे गाय का दुध डाला। बाद मे फिरसे बोधीवृक्ष हराभरा हो गया।सम्राट अशोक के वजह से अफगाणिस्ताण,इजिप्त,ग्रीक,चीन,जपान,थायलंड,ब्रम्हदेश,कश्मिर, भारत,श्रीलंका ऐसे कही देशो मे बौध्द धम्म का प्रचार किया। अफगाणिस्ताण के गांधार कला उन्नत हुई।और बामियान प्रांत मे बहोत सारे भ.बुध्द की मुर्तीया और चित्रकला तयार हो गई।भारत मे अजंता,वेलोरा और आंध्र प्रदेश के अमरावती मे कही शिलालेख ,गुफावो और देश के शिक्केपर बोधीवृक्ष के आकार और चित्र,शिल्प निकाले हुये नजर मे आता है।

पुष्पमित्रशृंगद्धारा ब्रहदरथ की हत्या : यह पंडित राजा ने इ.स.पू. 185 को अशोक के नाती ब्रहदरथ की धोके से हत्या की। उन्होने बौध्द धम्मपर बहोत सारे हमले किये है।कई भिक्षूवो को मार डाला। बोधीवृक्ष को नुकसान पहुचाया।कनिष्क ,राजा मिलींद और सम्राट हर्षवर्धनने बौध्द धम्म का प्रसार किया।बौध्द धम्मपर शंकराचार्य और राजा कुमारीलभट्ट उन्होने कही जानलेवा हमले किये।इ.स. 1203 तक डॉ.बाबासाहेब अंबेडकर कहते है की बौध्द धम्म का अस्तित्व था। बाद मे बौध्द धम्म भारत से नजरअंदाज सा हो गया।बाद मे भारत मे वैदिक धर्म के राज्य 'मनुस्मृती' के द्वारा चालू ही था।आगे चलकर विदेशी मुस्लिमयो का राज सातसो बरस तक था। 'बकत्यार' खिलजीने विश्व का नालंदा विश्वविद्यालय और ग्रंथालय को जलाया।

अंग्रेजी राज : भारत मे अंग्रेजी शासन 1757 मे आये।और 1857 को वो मजबूत हो गये।अंग्रेजोनो भारत मे कोर्ट,रेल्वे, विश्वविद्यालय,पोष्ट,तार,अस्पतल,और अंग्रेजी की पढाई सुरू किया। नया माहोल बन गया। अंग्रेजों ने सम्राट अशोक की शिल्प कला और उनके इतिहास की खोज की। 'फॅन्थेलर' ने सम्राट अशोक के शिलालेख 1785 खोजे।' जेम्स प्रिंसेपने' सम्प्रट अशोक के शिलालेख बार बार सात बरस तक पढने का प्रयास किया। बाद मे उनको पढाना आया। और विश्व सम्राट अशोक और बौध्द धम्म की जानकारी हो गई। बुध्दगया पहले विरान हुई थी।वहॉपर 'लॉर्ड बेंटिक'ने 1820 मे बुध्दगया की खोज की। उसके बाद 'अलेक्झांडर कॅनिहॅम' उन्होने 1861 मे बुध्दगया को दर्शन लिया। और खोज की। फिर 1829 मे 'जॉन स्मिथ' ने 'अजंता' गुफा की खोज की। अंग्रेजोने 1899 मे लुंबिनी की खोज की।

बुध्दगये का हाल अंग्रेजी साहित्यकार और लेखक 'एडविण आर्नाल्ड' उन्होने 1875 मे 'लाईट ऑफ आशिया' उन ग्रंथो मे अंग्रेजी मे लिखा।उनका प्रभाव अंग्रेजेपर हुआ।बाद उनका प्रभाव श्रीलंका के 'अनागारिक धम्मपाल' उनपर हुआ। उन्होने 1891 को बुध्दगया मुक्तीआंदोलन चलाया। और श्रीलंका मे से बोधीवृक्ष के लाया और बुध्दगया मे लगाया। बाद मे 1956 का डॉ. बाबासाहब अंबेडरने लाखो लोगो के साथ बौध्द धम्म की दिक्षा नागपूर मे स्वंय और बाद मे लोगो को दी। और धम्म को नवजिवन दिया।बाद मे नागपूर पे के दिक्षाभूमी मे भी बोधीवृक्ष लगाया गया। भारत सरकारने भ.बुध्द की 2500 वी जनमदिन अवसर पर पोष्ट के तिकट पर बोधीवृक्ष का निशान छपाया किया।यह बोधीवृक्ष के बारे मे सम्यक प्रकाशन दिल्ली उन्होने बेहतर ग्रंथ की निर्मीती की है।

बोधीवृक्ष एक औषधीयुक्त है। उसके पत्ते और लकडियॉ सेहत के लिये उपयुक्त है। भौतिक,मानसिक एंव महिलाये के रोग के बहोत उपयोगी है।बोधीवृक्ष एक 24 घंटे ऑक्सिजन देनेवाला पेड है। भ.बुध्द के वजह से विश्व मे बोधीवृक्ष का मान सन्मान किया जाता है।वही बोधीवृक्ष को सभीने पंचप्रणाम करना चाहिये।


सुरेश घोरपडे
मा.न्यायाधिश
मो.न.9921577605